

अपराध सरकारों के, माफी किसानों को

हाल ही में सरकार ों किसानों के
कर्ज माफ़ करने का कदम उठाया है।
इसी का प्राथमिक विश्लेषण
विकास संवाद द्वारा किया गया है।

मध्यप्रदेश में किसान और कर्ज से राहत*

भारत के संदर्भ में	संख्या
देश में कुल परिवार	147898800
देश में कुल कृषक परिवार	89350400
देश में कुल ऋणग्रस्त परिवार	43424200
देश में कुल कृषक परिवार (प्रतिशत में)	48.6
मध्यप्रदेश के संदर्भ में	
मध्यप्रदेश में कुल परिवार	9389800
मध्यप्रदेश में कुल किसान परिवार	6320600
मध्यप्रदेश में एक किसान पर औसत ऋण राशि	14218 रुपये
मध्यप्रदेश में कर्जे से ग्रस्त कुल किसान परिवार	3211000
मध्यप्रदेश में कर्जे से ग्रस्त कुल किसान परिवार (प्रतिशत में)	50.80 प्रतिशत
राज्य में कुल छोटे और सीमांत किसान (2 हेक्टर तक)	3775934
राज्य में कुल जोतों की संख्या	73.60 लाख
मध्यप्रदेश में आदिवासी कृषक	21.1 प्रतिशत
मध्यप्रदेश में दलित कृषक	21.1 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग कृषक	21.1 प्रतिशत
अन्य	19.4 प्रतिशत
मध्यप्रदेश में सभी किसानों की कुल ऋण राशि	8986 करोड़ रुपये
मध्यप्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों की कुल ऋण राशि	4029.54 करोड़ रुपये
मध्यप्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों पर संस्थागत ऋण	2337 करोड़ रुपये
मध्यप्रदेश में ऋणग्रस्तता किसान (कुल किसानी कर्ज में से)	
सामाजिक वर्ग	प्रतिशत
आदिवासी	15.9 प्रतिशत
दलित	18.6 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा	47.8 प्रतिशत
आय वर्ग	17.6 प्रतिशत

मध्यप्रदेश में छोटी और सीमांत भूमिधारित		
भूमि आकार	संख्या (लाख)	भारत
राज्य में सीमांत भूमि धारित (जोतें)	28.38 लाख	38.56 प्रतिशत
राज्य में छोटे भूधारिता (जोतें)	19.51 लाख	26.51 प्रतिशत
अन्य (जोतें)	25.71 लाख	34.93 प्रतिशत
कुल (जातें)	73.60 लाख	100 प्रतिशत

* किसानों की ऋणग्रस्तता का यह विश्लेषण भारत सरकार के नेशनल सेम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के नेशनल सेम्पल सर्वे के 59वें चक्र के आंकड़ों एवं निष्कर्षों के आधार पर विकास संवाद द्वारा किया गया है।

विकास संवाद विश्लेषण पत्र शृंखला - 26 vikassamvad@gmail.com

भू-स्वामित्व (मध्यप्रदेश एवं भारत)		
भूमि आकार	मध्यप्रदेश	भारत
0.01 हेक्टर	0.04 प्रतिशत (2530 परिवार)	0.013 प्रतिशत
0.01 से 0.40 हेक्टर	8.00 प्रतिशत (505648 परिवार)	29.9 प्रतिशत
0.41 से 1.00 हेक्टर	24.6 प्रतिशत (1554866 परिवार)	29.8 प्रतिशत
1.01 से 2.00 हेक्टर	27.1 प्रतिशत (1712890 परिवार)	18.9 प्रतिशत
2.01 से 4.00 हेक्टर	23.1 प्रतिशत (146005 परिवार)	12.5 प्रतिशत
4.01 से 10.00 हेक्टर	13.0 प्रतिशत (821678 परिवार)	6.4 प्रतिशत
10.00 हेक्टेयर से ज्यादा	0.39 प्रतिशत (24650 परिवार)	0.12 प्रतिशत

मध्यप्रदेश में कुल ऋण राशि		
भूमि आकार	मध्यप्रदेश	ऋण राशि
0.01 हेक्टर	0.04 प्रतिशत (2530)	1.54 करोड़ रुपये
0.01 से 0.40 हेक्टर	8.00 प्रतिशत (505648)	331 करोड़ रुपये
0.41 से 1.00 हेक्टर	24.6 प्रतिशत (1554866)	1340 करोड़ रुपये
1.01 से 2.00 हेक्टर	27.1 प्रतिशत (1712890)	2357 करोड़ रुपये
कुल राशि		4029.54 करोड़ रुपये
संस्थागत ऋण (कुल ऋण का 58 प्रतिशत)		2337 करोड़ रुपये

किसानों के वर्तमान कर्ज का कारण और उपयोग		
	मध्यप्रदेश	भारत
कृषि में पूंजीगत व्यय	47.2 प्रतिशत	30.6 प्रतिशत
कृषि में वास्तविक व्यय	21.3 प्रतिशत	27.8 प्रतिशत
गैर-कृषि व्यवसाय	0.14 प्रतिशत	6.7 प्रतिशत
उपभोग व्यय	9.6 प्रतिशत	8.8 प्रतिशत
विवाह/ सामाजिक व्यवहार	14.4 प्रतिशत	11.1 प्रतिशत
शिक्षा	0.01 प्रतिशत	0.08 प्रतिशत
स्वास्थ्य	3.6 प्रतिशत	3.3 प्रतिशत
अन्य व्यय	2.7 प्रतिशत	10.8 प्रतिशत

कर्ज के स्रोत		
	मध्यप्रदेश	भारत
सरकार	1.9 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत
सहकारी समितियां	16.9 प्रतिशत	19.6 प्रतिशत
बैंक	38.1 प्रतिशत	35.6 प्रतिशत
व्यावसायिक साहूकार	22.6 प्रतिशत	25.7 प्रतिशत

व्यापारी	9.0 प्रतिशत	5.2 प्रतिशत
रिश्तेदार/ मित्र	10.1 प्रतिशत	8.5 प्रतिशत
डॉक्टर/ वकील	0.05 प्रतिशत	0.09 प्रतिशत
अन्य	0.08 प्रतिशत	2.1 प्रतिशत
किसानों पर कितना कर्ज		
भूमि का आकार	भारत (कर्ज की राशि)	मध्यप्रदेश
0.01 हेक्टर से कम	6121 रुपये	5100 रुपये
0.01 से 0.4 हेक्टर	6545 रुपये	3335 रुपये
0.41 से 1.00 हेक्टर	8623 रुपये	7323 रुपये
1.01 से 2.00 हेक्टर	13762 रुपये	12467 रुपये
2.01 से 4.00 हेक्टर	23456 रुपये	19256 रुपये
4.01 से 10.00 हेक्टर	42532 रुपये	29642 रुपये
10. हेक्टेयर से ज्यादा	76232 रुपये	61800 रुपये

विभिन्न सामाजिक वर्गों के किसानों पर कर्ज की औसत राशि		
वर्ग	मध्यप्रदेश	भारत
आदिवासी	4812 रुपये	5506 रुपये
दलित	8910 रुपये	7167 रुपये
अन्य पिछड़ा वर्ग	15628 रुपये	13489 रुपये
अन्य वर्ग	25411 रुपये	18118 रुपये
कुल कर्ज	14218 रुपये	12585 रुपये

प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय (मासिक) और कर्ज की राशि (किसानों में)		
प्रति व्यक्ति मासिक व्यय	मध्यप्रदेश में किसानों पर कर्ज	भारत में किसानों पर कर्ज
000 से 225 रुपये	6305 रुपये	4446 रुपये
225 से 255 रुपये	9437 रुपये	6127 रुपये
255 से 300 रुपये	15322 रुपये	8591 रुपये
300 से 340 रुपये	14434 रुपये	8544 रुपये
340 से 380 रुपये	16067 रुपये	9100 रुपये
380 से 420 रुपये	9479 रुपये	9510 रुपये
420 से 470 रुपये	20889 रुपये	12873 रुपये
470 से 525 रुपये	17313 रुपये	15178 रुपये
525 से 615 रुपये	24338 रुपये	16529 रुपये
615 से 775 रुपये	22311 रुपये	20537 रुपये
755 से 950 रुपये	26690 रुपये	27630 रुपये
950 रुपये से ज्यादा	52418 रुपये	39058 रुपये
सभी वर्गों में	14218 रुपये	12585 रुपये

अपराध सरकार के, माफी किसान को

29 फरवरी को जब भारत के वित्तमंत्री देश का बजट संसद में पेश करने की तैयारी कर रहे थे तब चर्चाओं के हर मंच पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है थी कि बजट में कर्ज से ग्रस्त किसानों को कर्ज माफी का राजनीतिक तोहफा दिया जा सकता है। ऐसा होगा या नहीं यह स्पष्ट नहीं था पर संभावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र से बाजार के बैलों का मैदान (शेयर बाजार) में 100 अंकों की गिरावट आ गई यानी शेयर बाजार की मंशा के विपरीत है यह सब कुछ।

इसी दौरान व्यापारिक संगठनों और औद्योगिक विकास के विशेषज्ञों ने यह सवाल भी दाग दिया कि किसानों को दिये जाने वाले इस तोहफे की कीमत कौन वहन करेगा? उनका मानना था कि इस रियायत के एवज में उद्योगों रियायत कम होगी। वे केवल फायदा देख रहे थे कि उन्हें इस तथ्य से कोई सरोकार नहीं था कि 1993 से फरवरी 2008 की पंद्रह वर्षीय अवधि में 1.60 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, 48 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुये हैं, हर किसान पर औसत 20 हजार रुपये का कर्ज है और 42 प्रतिशत किसान कोई भी छोटा-मोटा विकल्प मिलने पर कृषि के काम की आहूति दे देना चाहते हैं।

अंततः वित्तमंत्री ने संभावनाओं पर से पर्दा हटाया और अपने राजनैतिक बजट में अंततः यह घोषणा की कि एक हैक्टेयर से कम भूमिधारी सीमांत किसानों और एक हैक्टेयर से दो हैक्टेयर की भूमि वाले देश के हर किसान के कर्ज 30 जून 2008 के पहले समाप्त कर दिये जायेंगे। इससे थोड़े बहुत नहीं बल्कि 3 करोड़ किसानों को पचास हजार करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इतना ही नहीं एक करोड़ अन्य बड़े किसानों द्वारा एकमुश्त ऋण समायोजन करने पर 25 प्रतिशत रियायत दी जायेगी, इस पर 10 हजार करोड़ रुपये का व्यय सरकार करेगी। ऐसा भी नहीं है कि बैंको पर इस घोषणा का बहुत भार पड़ेगा। 60 हजार करोड़ रुपये की यह धन राशि बैंको द्वारा दिये गये कुल कर्ज का 4 प्रतिशत मात्र है और इससे ढाई गुना ज्यादा राशि तो बड़े-बड़े व्यापारिक और आद्यौगिक घरानों ने गटक ली और डकार भी नहीं ली। डेढ़ लाख करोड़ रुपये की नान परफार्मिंग असेट्स की वसूली पर सरकार मौन रहती है और बाजार की ताकतें भी। ये वे संस्थान हैं जिन्होंने चुकानों में सक्षम होने के बावजूद राष्ट्रीय पूंजी का गबन किया है और उनकी मंशा पर सवालिया निशान भी है परन्तु वे ही गबनकर्ता आत्महत्या करते, गरीब, भुखमरी और अपमान के शिकार किसानों को रियायत दिये जाने पर विशेषज्ञ यह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि इसके बजाये बीज, खाद, सिंचाई और सस्ते ऋण की नीति पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि सवाल स्थाई विकास का है। मुद्दा स्पष्ट है कि उच्च और ताकतवर वर्ग जीवन को भोगने के लिए हैं परन्तु छोटे किसान और मजदूर विकास की परिभाषा का आदर्श बनने के लिए मजबूर किए जाते हैं। सरकार के इस कदम के बारे में सबसे पहले यह मान्यता बनानी होगी कि यह कोई “माफी” नहीं है।

कर्ज लेकर किसानों ने कोई अपराध नहीं किया था बल्कि सरकार स्वयं किसान विरोधी नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन की अपराधी है। यह एक तरह से प्रायश्चित की दिशा में पहला कदम है। इस कदम से उन 57 प्रतिशत किसानों को फायदा होगा, जिन्होंने बैंक, सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों से कर्ज लिया है, अब भी 43 प्रतिशत किसान इस राहत से वंचित रह गये हैं। दो हेक्टेयर की भूमि वाले किसानों पर 13762 रुपये का कर्ज है। मध्यप्रदेश के कुल कर्जदार किसानों में से 23 फीसदी ऐसे हैं, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि हैं। 4 हेक्टेयर तक के किसानों पर 23456 रुपये कर्ज है।

सपनों और सेवाओं का व्यापार करके अर्थिक लाभ को मोक्ष तुल्य लक्ष्य मानने वाले निजी क्षेत्र की यह मान्यता है किसानों और कृषि क्षेत्र में जाने वाली रियायत सबसे अप्रिय कदम है, जो सरकार उठाती है। परन्तु वे भूल जाते हैं कि 1991 में उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद भारत की तमाम सरकारों ने कृषि क्षेत्र के हकों को छीनकर बाजारवादी विकास को गति दी और इसी का परिणाम है कि डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करना पड़ी। और अनाज उगाने वाला किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। किसान को इस स्थिति में लाने का जतन शेयर बाजार की सूचीबद्ध कम्पनियों ने कम और सरकार ने ज्यादा किया है। हर तरह की रियायत, वह चाहे बिजली की हो, पानी की हो, करों की हो या फिर अधोसंरचनात्मक ढांचे की, उद्योग और सेवा क्षेत्र को दी गई। उद्योगों के विकास की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता है किन्तु यह विकास किस कीमत पर हो, यह विश्लेषण बेहद जरूरी है। कृषि क्षेत्र अपने आप कमजोर नहीं हुआ है बल्कि इसे कमजोर किया गया है ताकि छोटे और सीमांत किसान सस्ते श्रम के बाजार में नीलामी के लिये उपलब्ध हो और उनके अधिकार क्षेत्र से जमीनों को कानूनन छीना जा सके। यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नामक कार्यक्रम अपने आप में जमीन और संसाधनों की लूट जरिया बनाकर सामने लाया गया। किसानों की ऋण माफी के लिए खर्च होने वाली राशि से निजी और औद्योगिक क्षेत्र या अर्थशास्त्री चिंतित नहीं थे बल्कि वे चिंतित इस बात से थे कि सरकार के इस कदम से यह साबित हो जायेगा कि 17 सालों से चली आ रही उदारीकरण की आर्थिक नीतियों ने ही किसानों की यह दुर्दशा की है; जबकि इस तर्क को आधुनिक विकासवादी नकारते रहे हैं।

किसानों को रियायत मिली, उनके पक्ष पर यह एक अच्छा और तात्कालिक राहत देने वाला कदम है परन्तु सवाल यह है कि जिन नीतियों के कारण किसान इस स्थिति में आये उन नीतियों को बदलने के कौन से कदम सरकार उठा रही है; निःसंदेह बजट में सरकार ने ऐसे कोई खास संकेत नहीं दिये। अब भय यह भी है कि क्या यही किसान कुछ सालों बाद फिर वैसी ही स्थिति में नहीं आ जायेंगे!! विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का समर्थन करते हुये भारत भी 14 सौ से ज्यादा उपभोक्ता सामग्रियों के आयात में रियायत देता है। जब अमेरिका से आने वाला कपास

सस्ता होगा तो भारत के कपास उगाने वाले किसान को कौन पूछेगा? अमेरिका अपने कपास उत्पादकों को जबरदस्त रियायत देता है और यहां तक कि बिना उत्पादन के अमेरिकी किसान फायदे में रहते हैं परन्तु भारत में कृषि सब्सिडी लगातार घटाई गई है। ऐसे में 20 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसान धोखाधड़ी के शिकार होते हैं क्योंकि उनकी अपनी सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं करती है। अब भी तकलीफ की बात यह है कि सरकार ने केवल बैंकों द्वारा दिये गये कर्जों की माफी की घोषणा की है जबकि वास्तव में किसानों पर साहूकारों और निजी कर्जदाताओं का भी भारी कर्ज है। उम्मीद थी कि साहूकारी अधिनियम और अन्य बजट प्रावधानों के जरिये उस कर्ज की भी समाप्त किये जाने की पहल होती क्योंकि वह राशि सरकारी कर्ज से दो गुना से ज्यादा है। उम्मीद थी कि कृषि ऋण की ब्याज दर 7 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत कर दी जायेगी पर ऐसा नहीं हुआ।

यह भी तय है कि किसानों की ऋण माफी के कदम को विकास के कदम के साथ जोड़कर नहीं देखा गया है। सरकार ने 2.80 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान कृषि ऋण के लिये किया है किन्तु बाजार में किसान को उसकी फसल का लाभप्रद दाम मिले इसका प्रावधान नहीं है न ही कहीं भी यह घोषणा की गई है कि भारत के किसानों को आत्महत्या करने के लिये मजबूर करने वाले कृषि उत्पाद के आयात को नियंत्रित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 40 लाख छोटे और-सीमांत किसान हैं जिनके पास औसतन 0.91 हेक्टेयर भूमि है और केवल 26 प्रतिशत ही कृषि योग्य है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में माना गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 1982-83 में 36.4 प्रतिशत थी जो वर्ष 2006-07 में घटकर 18.5 प्रतिशत रह गई है। इसके बावजूद कृषि ने आधी अरब से अधिक आबादी को निरन्तर सहायता प्रदान की है और कार्यबल के 52 प्रतिशत को रोजगार मुहैया कराया है। परन्तु कृषि उत्पादन की बढ़ोत्तरी दर वर्ष 1990-2007 के दौरान 1.2 प्रतिशत गिर गई जो जनसंख्या के औसतन 1.9 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी दर की तुलना में कम है। अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है पर उत्पादन कम बढ़ रहा है अनाजों की खपत 1990-91 में प्रतिदिन 468 ग्राम से घटकर वर्ष 2005-06 में 412 ग्राम प्रतिव्यक्ति हो गई है। जिस दौर उत्पादन कम हो रहा है उसी दौर में वित्तमंत्री विकास दर तेज होने का दावा कर रहे हैं यानी कृषि की कीमत पर देश का विकास हो रहा है। कुपोषण बढ़ा, खून की कमी के शिकार बढ़े, खाद्यान्न उपलब्धता कम हुई, किसानों ने आत्महत्याएँ की पर देश विकसित हुआ यह कैसा विकास ?